फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 324 प्रभात जयपुर, शनिवार 27 जून, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

To Be Responsible

Talk about mentoring? Here is mentoring for you. Teach, equip and trust. To trust means to give responsibility

The Mona Lisa and Michael Jackson

The Tragic Tale at Pichola Lake, Udaipur

एआईसीसी में काफी परिवर्तन हुए, पर इसमें राहुल के दलित प्रेम के अलावा कुछ खास नज़र नहीं आया

एक ब्राह्मण, अविनाश पाण्डे को यूपी के प्रभारी पद से हटाया और उसकी जगह राजेन्द्र पाल गौतम, एक दलित को जिम्मेवारी सौंपी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। कांग्रेस ने राहुल गांधी के दलित प्रेम और दलित एजेण्डे को आगे बढ़ाते हुये, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) में फेरबदल की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

हिंदी भाषी क्षेत्र के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एआईसीसी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, जो ब्राह्मण हैं, की जगह दलित नेता राजेन्द्र पाल गौतम को नियुक्त किया गया है।

राहुल गांधी का मकसद साफ है कि वे उत्तर प्रदेश में दलित वोटों को फिर से कांग्रेस के पाले में लाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि राजेन्द्र पाल गौतम यह काम कर सकते हैं।

राजेन्द्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके तुरंत बाद उन्हें कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष बनाया गया और अब उन्हें उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस फैसले ने कांग्रेस के कई नेताओं को हैरान कर दिया है।

- गौतम आम आदमी पार्टी को छोड़कर कुछ समय पूर्व ही कांग्रेस में आए थे, और बड़े तूफानी तरीके से ऊपर चढ़ते हुए, अब यूपी के प्रभारी बने हैं।
- हरियाणा में भी एआईसीसी के पूर्व सचिव सुनील दत्त को प्रभारी नियुक्त किया गया है। पर, उनकी नियुक्ति से भी कुछ उत्साह का संचार नहीं हुआ, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति पर, हुड्डा परिवार आधिपत्य है।
- उड़ीसा में अजय कुमार लालू को हटाकर लालजी देसाई को इंजार्च बनाया गया है। इस नियुक्ति से भी कोई खास चमत्कारिक उपलब्धि होने की आशा नहीं है।
- अतः, ऐसा लगता है कि एआईसीसी के ये परिवर्तन, केवल परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए हुए हैं, कुछ खास रिजल्ट की आशा के कारण नहीं किये गये हैं।

बी. के. हरिप्रसाद को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद, पूर्व एआईसीसी सचिव सुनील दत्त को हरियाणा का एआईसीसी प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में लगभग पूरा संगठन हुड्डा परिवार के प्रभाव में माना जाता है, इसलिए वहां किसी और के लिए बहुत अधिक भूमिका नहीं बचती। ऐसे में यह नियुक्ति लगभग औपचारिक मानी जा रही है।

तीसरा राज्य, जहां बदलाव किया गया है, वह ओडिशा है, जहां कांग्रेस की स्थिति अब भी कमजोर बनी हुई है।

अजय कुमार लल्लू को ओडिशा के एआईसीसी प्रभारी पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह लालजी देसाई को नया प्रभारी बनाया गया है।

अब तक लालजी देसाई सेवा दल के मुख्य ऑर्गनाइज़र थे। अब वे ओडिशा की जिम्मेदारी संभालेंगे।

पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास को अब सेवा दल का मुख्य ऑर्गनाइज़र बनाया गया है।

श्रीनिवास कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार और उनके भाई सुरेश कुमार के करीबी हैं।

अजय कुमार लल्लू कभी राहुल गांधी के चहेते हुआ करते थे, लेकिन, उनके कई अन्य करीबी नेताओं की तरह, अब वे भी राहुल गांधी की नज़रों से उतर गए हैं। उन पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी हैं और ओडिशा में भक्ति

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वेनेज़ुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 589 पहुंची

काराकास, 26 जून। वेनेज़ुएला में बुधवार को आए दो शक्तिशाली भूकंपों के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ ने शुक्रवार को बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ कर 589 हो गई है, जबकि 2,980 लोग घायल हुए हैं। हजारों लोगों के अब भी लापता होने की आशंका के बीच राहत एवं बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राजधानी काराकास के उत्तर में स्थित तटीय राज्य ला गुएरा सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां कम से कम 100 इमारतें पूरी तरह ढ ह गई हैं। स्थिति की

- राजधानी के उत्तर में स्थित तटीय राज्य ला गुएला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, जहां 100 इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं।

गंभीरता को देखते हुए पूरे, क्षेत्र को "आपदा क्षेत्र" घोषित कर दिया गया है। प्रभावित इलाकों में सेना की तैनाती की गई है और भोजन, पेयजल, दवाइयों तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं, जिसके कारण मृतकों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (आईओएम) के अनुमान के अनुसार,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंगाल के मु.मंत्री बेहिचक "हिन्दू फर्स्ट" की नीति का अनुसरण कर रहे हैं

उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह कहना शुरु किया कि भाजपा की जीत "हिन्दुत्व" की जीत है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। भाजपा-शासित गुजरात और उत्तराखंड में "समान नागरिक संहिता" (यूसीसी) लागू हो जाने के बाद, जब असम सरकार ने भी इसे अपना लिया, तो अब पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार के भी पीछे रहने की संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार, शुभेन्दु अधिकारी सरकार सोमवार को राज्य विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य सभी समुदायों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु तय करना और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य बनाना है।

सूत्रों ने बताया कि विधेयक के मसौदे में बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने तथा महिलाओं को, उम्र की परवाह किए बिना, संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार देने का भी प्रावधान है।

9 मई को मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से ही शुभेन्दु अधिकारी ने अपनी सरकार के "हिंदू फर्स्ट" एजेंडे को लेकर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। नई सरकार ने सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध

- शुभेन्दु अधिकारी ने सत्ता में आते ही सड़कों पर नमाज़ अदा करने पर प्रतिबंध लगाए तथा 75 प्रतिशत मुस्लिम जातियों का ओबीसी स्टेटस रद्द किया।
- मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ का अभियान चलाया।
- अल्पसंख्यक गतिविधियों व मदरसा शिक्षा के बजट को 62 प्रतिशत घटाया और यह प्रचारित किया कि सरकार की नीति है कि बच्चों को प्रोफेशनल व तकनीकी शिक्षा की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और मदरसा शिक्षा पर निर्भरता कम की जाए।
- बंगाल के लिए प्रस्तावित यूसीसी विधेयक, "लिव-इन रिलेशनशिप" के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करेगा तथा समुदायों के लिए तलाक की एक "कॉमन" प्रक्रिया लागू होगी।

या कड़े नियंत्रण लगाए हैं तथा धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पाबंदियां लगाई हैं। राज्य सरकार ने गोहत्या पर नियंत्रण को और सख्त करने के लिए भी कदम उठाए हैं और 75 से अधिक मुस्लिम समुदायों का अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा भी रद्द कर दिया है।

शुभेन्दु अधिकारी राज्य में भाजपा की जीत को कई बार "हिंदुत्व की जीत" बता चुके हैं। उन्होंने अनेक अवसरों पर हिंदू एकता और सनातन धर्म के प्रोत्साहन का आ ान भी किया है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अतिक्रमण-विरोधी अभियान भी चलाए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026-27 के राज्य बजट में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली की "शील्ड" (रक्षा कवच) के जगह-जगह नष्ट होने से भारी आँधियों का सिलसिला शुरु हुआ है?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। इस जून में दिल्ली को बार-बार धूल भरी आँधियों का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह है -शहर की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार, यानी अरावली पर्वतमाला का धीरे-धीरे क्षय होना। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी लगभग 650 किलोमीटर लंबी पहाड़ी श्रृंखला दिल्ली से हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है।

सदियों से अरावली थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार का काम करती रही है। लेकिन अब यह दीवार धीरे-धीरे टूट रही है और मामला अदालत तक पहुंच चुका है।

नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार "अरावली" की एक कानूनी परिभाषा तय की और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नई खनन

- 650 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला, जो दिल्ली से हरियाणा व राजस्थान होते हुए गुजरात तक जाती है, अब कई स्थलों पर ढह गई है। इसका नतीजा था कि 23 जून को लगभग ढाई बजे दोपहर में, भारी आँधी के कारण "रेड अलर्ट" घोषित हुआ था, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान में।
- वैज्ञानिकों का मत है, ये आँधियाँ एक प्राकृतिक प्रसंग हैं: पर, ग्लोबल वॉर्मिंग से ये आँधियाँ और तीखी, धार वाले चाकू जैसी पैनी हो गई हैं।
- गर्मी के कारण, काफी एनर्जी (ऊर्जा) वातावरण में इकट्ठी हो जाती है। जिससे अस्थिरता पैदा होती है और यह असंतुलन इन आँधियों को जन्म देता है और पनपाता है।

लीज पर तब तक के लिये रोक लगा दी, जब तक कि टिकाऊ खनन की कोई सही योजना तैयार न हो जाए। इसका उद्देश्य खनन और निर्माण कार्यों पर रोक लगाना था, जिनकी वजह से इस पर्वत श्रृंखला में दरारें या खाली जगहें बन गई हैं।

23 जून को दोपहर करीब 2:30 बजे एक भीषण आंधी आई। इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डीजीपी राजीव शर्मा को पितृ शोक

जयपुर, 26 जून। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के पिता सुरेश चंद शर्मा का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। स्व. शर्मा पिछले काफी समय से

- गमगीन माहौल में नोएडा में अंतिम संस्कार हुआ।

अस्वस्थ चल रहे थे। शुक्रवार को जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन का समाचार मिलते ही, प्रशासनिक, पुलिस एवं सामाजिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई।

गमगीन माहौल के बीच नोएडा में उनका अंतिम संस्कार हुआ। अनेक वरिष्ठ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका के रिज़र्व बैंक के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन वाकई में सैन्ट्रल बैंकर्स के बैंकर थे

ग्रीनस्पैन का अमेरिका के फायनैंशियल सिस्टम की ताकत में अटूट विश्वास था, जो 9/11 के संकट में बेखूबी देखा गया था

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। केन्द्रीय बैंकर तो बहुत हुए हैं, लेकिन एलन ग्रीनस्पैन, चार दिन पहले 100 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ, वास्तव में केन्द्रीय बैंकरों के भी केन्द्रीय बैंकर थे।

अमेरिका के फैडरल रिज़र्व के अध्यक्ष का पद अपने वैश्विक प्रभाव के कारण किसी भी अन्य केन्द्रीय बैंक प्रमुख से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एलन ग्रीनस्पैन ने इस पद की गरिमा और प्रभाव को पूरी दक्षता के साथ निभाया।

उन्होंने ऐसे समय में यह जिम्मेदारी संभाली, जब उनके पूर्ववर्ती पॉल वोल्कर पहले ही मौद्रिक प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित कर चुके थे। ऐसे दिग्गज की विरासत को आगे बढ़ाना ग्रीनस्पैन के लिए एक बड़ी

- ग्रीनस्पैन का मानना था कि अगर फायनैंशियल मार्केट में संकट हो, तो बैंकों का काम होता है, पैसे की आवक व उपलब्धि निरंतर बरकरार रखें, क्योंकि कालांतर में कुछ समय बाद मार्केट अपने आप स्वस्थ हो जाएगा और अधिकतर ऐसा ही होता है।
- ग्रीनस्पैन की यह फिलॉसफी व सोच उनके रिटायरमैंट के बाद भी अमेरिका के फायनैंशियल सैक्टर के गवरनैंस की आत्मा है।

चुनौती थी।

लेकिन पद संभालने के कुछ ही समय बाद, ग्रीनस्पैन ने मौद्रिक नीति के तय नियमों को किनारे रखकर अपनी सोच के अनुसार काम करना शुरू किया।

ग्रीनस्पैन ने वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध "लाइट टच रेगुलेशन" यानी न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की नीति अपनाई। उन्होंने वित्तीय क्षेत्र के विस्तार और बाजार में पर्याप्त तरलता (लिक्विडिटी) बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि आर्थिक गतिविधियां सुचारु रूप से चलती रहें। जब तक स्थिति नियंत्रण में रही, यह रणनीति सफल साबित हुई।

लेकिन समय के साथ यह व्यवस्था अत्यधिक दबाव में आ गई और अंततः बड़े वित्तीय संकट में बदल गई। वर्ष 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के लिए अक्सर ग्रीनस्पैन को जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि, वे 2006 में ही फैडरल रिज़र्व के चेयरमैन का पद छोड़ चुके थे।

दरअसल, इस संकट की नींव उनके कार्यकाल के दौरान ही पड़ चुकी थी। ग्रीनस्पैन को बाजार की ताकत पर गहरा विश्वास था, जो लगभग अंधविश्वास का रूप ले चुका था। उनके कार्यभार संभालते ही शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई, लेकिन उन्होंने बाजार में पर्याप्त नकदी बनाए रखी और आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने की नीति अपनाई। उस समय यह रणनीति सफल रही।

11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के समय एलन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति ने हरिद्वार के काली मंदिर में पूजा की

हरिद्वार, 26 जून। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जूमा ने शुक्रवार को धर्मपत्नी एवं परिजनों के साथ तीर्थनगरी हरिद्वार में श्री दक्षिण काली मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर के

- महामंडलेश्वर कैलाशानन्द गिरी ने पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 2029 के चुनाव में विजयी होने का आशीर्वाद दिया।

परमाध्यक्ष एवं निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद लिया।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जूमा के मंदिर पहुंचने पर स्वामी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऑयल संकट कुछ कम हुआ, तो कमज़ोर मानसून महंगाई घटने नहीं देगा?

साउथ-वेस्ट मानसून से भारत की 70 प्रतिशत बारिश की आवश्यकता पूरी होती है और पर्याप्त बारिश भारत की 300 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर इकॉनमी को चलाती है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 जून। पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में अचानक आई तेज़ी के बाद, भारत ने अभी राहत की सांस लेना शुरू ही किया था कि चिंता की एक और वजह सामने आ रही है - मॉनसून।

अर्थशास्त्री और नीति-निर्माता लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि सामान्य से कम मॉनसून और "अल नीनो" मौसम पैटर्न, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में महंगाई की अगली बड़ी वजह बन सकते हैं।

चिंता सिर्फ़ बारिश कम होने की नहीं है। इसका असर खाद्य पदार्थों की कीमतों, ग्रामीण आय, ग्राहकों की मांग, ब्याज दरों और अंततः आर्थिक विकास पर पड़ सकता है।

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून, भारत में सालाना बारिश का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा लेकर आता है, और देश की करीब 300 अरब डॉलर की कृषि अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा माना जाता है। कमज़ोर मॉनसून से फ़सल की पैदावार कम हो सकती है, चावल, दाल, सब्ज़ियों और खाने के तेल जैसी ज़रूरी चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं, और ग्रामीण भारत में खर्च करने की क्षमता कम हो सकती है, जहाँ लाखों परिवार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खेती पर निर्भर हैं।

- मौसम विभाग के अनुसार, इस वर्ष 2015 के बाद सबसे कमज़ोर मॉनसून है।
- इस कमज़ोर मानसून के कारण खाद्य पदार्थों की कीमत तो बढ़ेगी, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत इस संकट में लगभग 34 मिलियन रोज़गार के अवसर खो देगा।
- तो क्या महंगाई की दृष्टि से भारत की स्थिति आसमान से गिरे, तो खजूर पर जा कर अटकने जैसे हो जाएगी?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष सामान्य औसत की तुलना में केवल 90 प्रतिशत बारिश का अनुमान जताया है, जिससे ये चिंताएं और बढ़ गई हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह 2015 के बाद मॉनसून का सबसे खराब प्रदर्शन होगा। यह समय इसलिए भी बहुत अहम है, क्योंकि सिंचाई परियोजनाओं, वॉटरशेड विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में दशकों के निवेश के बावजूद, भारत का लगभग 45 प्रतिशत खेती वाला इलाका अभी भी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। यह कमज़ोरी अब ज़मीनी स्तर पर भी दिखने लगी है।

देश के कई बड़े जलाशयों में जून की शुरुआत में पानी का स्तर काफ़ी कम था, जिससे खरीफ़ की बुवाई के लिए उपलब्ध पानी का भंडार (बफ़र) सीमित हो गया है। जलाशय में पानी कम होने से न सिर्फ़ खेती पर असर पड़ता है, बल्कि पीने के पानी की सप्लाई, पनबिजली उत्पादन और औद्योगिक इस्तेमाल पर भी असर पड़ता है। कई राज्यों में बुवाई में देरी, कम क्षेत्र में खेती और, अगर बारिश अनियमित रही तो, फ़सल की पैदावार कम होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं।

महंगाई पर इसके असर काफ़ी बड़े हो सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत में खाद्य महंगाई हमेशा से सबसे संवेदनशील आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों में रही है। भले ही वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएं, लेकिन खराब मॉनसून घरेलू स्तर पर खाने-पीने की चीज़ों की सप्लाई कम करके उन फ़ायदों को तेज़ी से खत्म कर सकता है। जानकारों का कहना है कि सब्ज़ियों, दालों और अनाजों की कीमतों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। अगर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने दो विमानों में राहत सामग्री वेनेज़ुएला भेजी

नई दिल्ली, 26 जून। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद, भारत ने संकट की इस घड़ी में मानवीय सहायता के लिए मदद का हाथ बढ़ाया

- विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर आगे भी सहयोग जारी रहेगा।

है। भारतीय वायुसेना के दो विमान ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत शुक्रवार को आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा उपकरण लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बताया कि राहत सामग्री में एक फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, 35 टन से अधिक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)